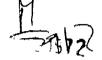


श्राकास हो प

EXTRAORDINARY



भाग 1--सग्छ 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਧੂਰ 102)

नई दि ली, सो नार ।ई 8 1972, विशाल 18, 1891

No 102]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 1972/VAISAKH \ 18, 1894

इस भाग में भिन्न (ष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के कर में रखा जा जह ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th May 1972

No. F.65(11)Ins.III/1/72.—As a first step towards the nationalisation of general insurance business, the management of the undertakings of insurance carrying on general insurance business (with certain exceptions) was taken over, with effect from the 13th May, 1971, under the General Insurance (Emergency Provisions) Act, 1971. Necessary legislation for the next step, namely, taking over the ownership will follow soon.

2. The terms and conditions of service of employees in general insurance vary widely. It is necessary that uniform pay scales and service conditions are evolved and all employees coming into the nationalised set-up integrated into them. Government have, therefore, decided to constitute a Committee to go into the matter

in all its aspects and make suitable recommendations. The Committee will consist of the following:—

- (1) Shri K. P. Mathrani, ICS(Retd)-Chairman.
- (2) Shri C. S. Anantapadmanabhan, Controller of Insurance—Member.
- (3) Shri B. G. Idnani-Member Secretary.
- 3. The following will be the terms of reference of the Commitee:—
- (1) (a) To examine the existing organisational and administrative set-up in general insurance business;
 - (b) to suggest the principles which should govern the pay-scales and other terms and conditions of service to be fixed for the nationalised set-up; and
 - (c) to recommend suitable designations, integrated scales of pay and other terms and conditions of service in the nationalised set-up, having regard to the nature of work and levels of responsibility.
- (ii) To recommend the general and technical qualifications and also nature and length of experience for determining the eligibility of such employees for holding posts or specified categories of posts in the integrated set-up.
 - (iii) To recommend the criteria for-
 - (a) absorption of the employees of those insurers, the management of whose undertakings has been taken over by Government and also of other insurers and Government Departments whose general insurance business may be transferred to the nationalised set-up, against specific grades and scales of pay; and
 - scale of pay in such set-up taking into account, inter allia, their qualifications, experience, the levels of responsibility shouldered by them as also their record of performance.
- √(v) To recommend, in particular, in respect of the officials of the rank and/or nouldering the responsibility of Assistant Branch Managers or posts of corresponding category (whether on the administration or development side) and officials of higher rank or responsibilities who are in the employ of the insurers and departments referred to in sub-clause (iii) above, at what level each of such officials may be absorbed in the integrated set-up and the inter se seniority of such of them as are considered suitable for absorption in the integrated set-up at various levels.
- (v) To make any other recommendations, incidental or aucillary to the foregoing which the Committee may deem fit.
- 4. The Committee will devise its own procedure for transacting its business and may call for such information and may take such evidence as it may consider necessary. It may also, in its discretion, interview any person who may be affected by any recommendation which the Committee is likely to make.
- 5. The Committee will have its Headquarters at New Delhi and will function as an attached officer of the Ministry of Finance. It has started functioning from 1st May, 1972.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all concerned and that be published in the Gazette of India for general information.

वित मंत्रालय

(राजस्य और मीभा विभाग)

सं करण

नई दिल्ली, 8 मई, 1972

सं• का• 65(11) वी T-III/1/72. — विविध वीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण की दिशा में त्रथम व्यव्य के रूप में, विविध वीमा कारोबार भलाने वाले वीमा-उपक्रमों का प्रवन्ध, साक्षारण बीमा (आपात उपवन्ध) अभिनियम 1971 के अन्तर्गत, (कृष्ठ अपनायों को छोड़ कर) 13 मई, 1971 से सरकार में अनने हाथों में ले लिया था। स्वामित्व ग्रहण करने के श्रमले चरण के लिये आवश्यक विधान शीध पेश किया जायगा।

- 2. विविध श्रीमा कम्पितमों के कर्म नारियों की सेवा की शर्ते वड़ी भिन्नताएं लिए हुए हैं। यह भावश्यक है कि एक रूप वेतनमान श्रीर सेवा की शर्ते तैयार की जायं, श्रीर राष्ट्रीयकृत संरचना के श्रन्तगंत हाने वाल सभी कर्मचारियों का उनमें समावेश किया जाय। इसलिये, इसे मामले में सभी पहलुश्रों से विचार करने श्रीर उपबुक्त सिफारिशों करने के लिये सरकार ने एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है। समिति में मिम्नलिखित हिम्मिलत होंगे :---
 - (1) श्री के बी भगरानी, आई० सी एस (सेबा निवृक्त) . ग्राध्यक्ष
 - (2) श्री ती एत अन्तरतपद्मनाभन्, बीमा निवन्त्रक , , सदस्य

 - मिति में निर्देश-पद निम्नलिखित होंगे :——
 - (i) (क) विविध सीमा कारोशार की वर्तभान संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना की जांच करना:
 - (ख) राष्ट्रीयस्तृत सरचना के ग्रधीन वेतनमानों और सेवा की ग्रन्य शर्तों श्राधि की क्यवस्था जिन सिद्धान्तों के श्रनुसार होनी चाहिये उनके बारे में सुझाब देना;
 - (ग) कार्य के स्वरूप और जिस्मेक्षारी के स्तरों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीयकृत संरचना में उपयुक्त पदनामों, एकीकृत वेतन-मानों और सेवा की अन्य प्रतीं आदि के बारे में निकारिश करना।
 - (ii) एकीक्कत संरचना में, पदों में प्रथमा विनिर्दिश्ट पद-वर्गों में नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की पासता का निर्णय करने के प्रयोजन से सामान्य श्रीर तकनीकी प्रहेताश्रों की तथा प्रवृश्व के स्वरूप एवं ग्रवधि की भी सिफारिश करना ।
 - (iii) निम्लानिकित के सम्बन्ध में मानदण्ड की सिफारिश करना—
 - (क) जिन बीमा कम्पनियों की प्रमन्ध व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, उन के और जिन अन्य बीमा कम्पनियों तथा यरकारी विभागों का विविध बीमा कारोबार, राष्ट्रीयहृत संरचना की अन्तरित किया जाम, उनके भी कर्मचारियों का विशिष्ट प्रेडों भीर बेंचन-मानों में समावेश करना; भीतं

- (ख) श्रन्य बातों के साथ साथ, कर्मचारियों की योग्यताश्चों, श्रनुभव, उनके द्वारों वहन की गयी जिम्मेदारी के स्तरों श्रौर उनके कार्य-कोशल के रिकार्ड को दृष्टि में रखते हुए उक्त सर्चना में उनकी वरिष्ठता तथा वेतनमानों के नियमन के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण:
- (iv) महायक शखा प्रबन्धक के पद पर प्रथवा उससे उच्चतर पद पर कार्य करने वाले श्रीर/प्रथवा उस पद अथवा उससे उच्चतर पद की जिम्मेदारियों को वहन करने वाले जो श्रिधिकारी उपर्युक्त खंड (ii) में उन्लिखित बीमा कम्पनियां श्रीर त्रिभागों की नौकरी में (चाहे प्रशासन पक्ष में हो श्रथवा विकास पक्ष में) हैं, उनके सम्बन्ध में विशिष्टतः यह स्पितिश्य करना की एकीकृत सरचना में ऐसे प्रत्येक श्रिधिकारी का किस स्तर पर समाहार किया आए, श्रीर जिन कर्मचायों को एकीकृत सरचना में विशिष्ट स्तरों पर समाहित करने के लिए उपर्यक्त समझ। जाए उनकी परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण;
- (v) ऐसी भ्रन्य सिफारिशें करना जो उपयंक्त की प्रासंगिक भ्रथवा भ्रनुषंशी हों भ्रौर जिन्हें समिति उपयुक्त सम्झें।
- 4. श्राने कार्य संचालन के लिए कार्योवधि , समिति स्वयं ही निश्चित करेगी तथा समिति ऐसी सूचना प्राप्त कर सकेगी एवं होसा साक्ष्य ले सकेगी, जिसे वह श्रावण्यक समझें । वह श्रपने विवेकानुणार ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात भी ले सकेगी जिस पर समिति झारा की जाने वाली किसी संभावित सिफारिश का श्रमर पड़ता हो ।
- 5. समिति अपना मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में रखेगी तथा विन मन्नालय के सम्बद्ध कार्याल (के रूप में कार्य करेगी । समिति ने 1 मई, 1972 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

ग्रादेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतितिपि सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की भेज दी जायोतथा इसे श्राम भूचना के सिए भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाये।

> एम० श्रार० धादीं, सन्विधः